Jagran

16 thousand vacancies, recruitment process starts at 9000

विकास गुसाई, देहरादून: सरकारी रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे बेरोजगारों को कुछ राहत मिल सकती है। प्रदेश के 89 सरकारी महकमों में 15907 पद रिक्त हैं। यह आंकड़ा 16 हजार तक पहुंच सकता है। 27 महकमों से रिक्त पदों की सूचना का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि, बैकलॉग के पदों की संख्या में कमी आई है। बैकलॉग के महज 1113 पद ही रिक्त होने की सूचना अब तक कार्मिक को मिली है। कुल रिक्त पदों में से नौ हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शेष बचे रिक्त पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर मंथन चल रहा है।

प्रदेश के सरकारी महकमों में रिक्त पदों की संख्या में कमी आई है। इन महकमों में तकरीबन 80 फीसद पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। अपडेट जानकारी के मुताबिक अब केवल 20 फीसद पद ही रिक्त चल रहे हैं। इनमें से भी आधे से अधिक में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी महकमों में आरक्षित पदों के बैकलॉग के साथ ही शेष रिक्त पदों को भरने के निर्देश जारी किए थे। मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने सभी विभागों से रिक्त पदों की सूचना तलब की। इसके तहत अभी तक तकरीबन 89 विभागों ने शासन को रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करा दी है। इसके मुताबिक अभी इन विभागों में 15907 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें भी सबसे अधिक पद फिलहाल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में रिक्त हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें बैकलॉग के केवल 1113 पद ही रिक्त चल रहे हैं। फिलहाल, कार्मिक विभाग इस सूची को और अपडेट करने में जुटा हुआ है, ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो सके। जिन विभागों ने अभी तक शासन को सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, उनके विभागीय सचिवों को मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की ओर से एक पत्र जारी कर जल्द सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सचिव कार्मिक आनंद वर्द्धन का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में तकरीबन 80 फीसद पद भरे हुए हैं। विभागों से रिक्त पदों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। इसके अनुसार 15907 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें से भी तकरीबन नौ हजार पदों में भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। शेष रिक्त पदों पर भी जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

पदों की स्थिति
प्रदेश में कुल पद - 75933
रिक्त पद - 15907 (27 विभागों से अभी सूचना आना बाकि)
रिक्त पदों की स्थिति
सामान्य श्रेणी - 8803

अनुसूचित जाति - 4164
अनुसूचित जनजाति - 812
अन्य पिछड़ी जाति - 2128
इन विभागों से नहीं मिली सूचना

विधानसभा सचिवालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल, अधीनस्थ जिला न्यायालय एवं कुटुंब न्यायालय, महाधिवक्ता कार्यालय, लोक सेवा अधिकरण कार्यालय, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कार्यालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, महाप्रशासक कार्यालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, उत्तराखंड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ परिवार न्यायालय/विधिक सेवा समिति, लोक आयुक्त संगठन, फर्म सोसायटी एवं चिट्स, फर्म सोसायटी एवं चिट्स, बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, वित्त आयोग निदेशालय, संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ की स्थापना, निदेशालय कोषागार अधिष्ठान, सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा, कोषागार अधिष्ठान, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, राज्य शैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन, निदेशालय प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुड़की, श्रम तथा रोजगार-प्रशिक्षण, श्रम तथा रोजगार- सेवायोजन, श्रम श्रमायुक्त संगठन, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखंड रुड़की, खनन तथा धातु कर्म उद्योग।